ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 214-217

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

बदलते परिदृश्य में मानव विकास की ओर अग्रसर भारत

शशिबाला

असि0 प्रोफे0, अर्थशास्त्र विभाग, म. गां. काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.) भारत

Received- 22.11.2019, Revised- 25.12.2019, Accepted - 28.12.2019 E-mail: drshashibala9@gmail.com

सारांश : *fHDI की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा निर्मित वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में पाई जाती है । ये 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किए गए और लॉन्च किए गए थे और उनका स्पष्ट उद्देश्य था '' राष्ट्रीय आय लेखांकन से विकास केंद्रित अर्थशास्त्र के लोगों को केंद्रित करना '' । मानव विकास रिपोर्ट का निर्माण करने के लिए महबूब उल हक ने पॉल स्ट्रीटन , फ्रांसेस स्टीवर्ट, गुस्ताव रानिस, कीथ ग्रिफिन, सुधीर आनंद और मेघनाद देसाई सहित विकास अर्थशास्त्रियों के एक समूह का गठन किया । नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मानव क्षमताओं पर अपने काम में हक के काम का उपयोग किया । हक का मानना था कि जनता, शिक्षाविदों और राजनीतिज्ञों को समझाने के लिए मानव विकास के एक सरल समग्र उपाय की आवश्यकता थी कि वे न केवल आर्थिक प्रगति से बल्कि मानव कल्याण में सुधार से विकास का मूल्यांकन कर सकें ।*

कुंजी शब्द– परिदृश्य, उत्पत्ति, मानव विकास, लेखांकन, मानव क्षमता, जनता, शिक्षाविद्, राजनीतिज्ञ, मानव कल्याण।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुताबिक 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई है और 189 देशों के बीच इसकी रैंकिंग 129 हो गई है । यूएनडीपी की भारत में स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा ने कहा कि भारत में 2005 – 06 से 2015 – 16 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया । अभी भी हालांकि भारत की स्थिति ठीक नहीं है । यह श्रीलंका, ईरान तथा चीन जैसे देशों से भी काफी पीछे है । वहीं, पाकिस्तान इस सूची में 3 पायदान ऊपर चढ़ने में कामयाब हुआ हैं, जबकि बांग्लादेश 2 पायदान ऊपर चढ़ा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 130 थी। तीन दशकों से तेज विकास के कारण यह प्रगति हुई है, जिसके कारण गरीबी में कमी आई है । साथ ही जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में बढ़ोतरी के कारण भी रैंकिंग सुधरी है।

मानव विकास सूचकांक के आधार पर दक्षिण एशियाई देशों में भारत का तीसरा स्थान है, श्रीलंका और मालदीव के बाद । भारत का एचडीआई (0.624) विश्व के एचडीआई औसत (0.717) से काफी कम जबकि दक्षिण एशिया के एचडीआई औसत (0.621) से बस थोड़ा अधिक है । साल 2010 से असमानता – समायोजित मानव विकास सूचकांक (आईएचडीआई) को भी मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया है । नॉर्वे, स्विटजरलैंड भ्क्प् रैकिंग में टॉप पर रैकिंग में नॉर्वे, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी टॉप पर हैं, जबकि नाइजर, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, चाड और बुरुंडी काफी कम HDI वैल्यू के साथ फिसड्डी देशों में शुमार हैं । भारत का एचडीआई वैल्यू (0.640) दक्षिण एशिया के औसत 0. 638 से थोड़ा सा ऊपर है ।

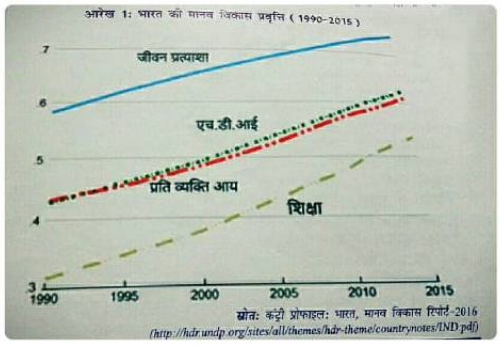

स्रोत– कंट्री प्रोफाइल : भारत , मानव विकास रिपोर्ट – 2016 (http : / / hdr - undp - org / sites / all / themes / hdr & theme / countrynotes / IND - pdf)

वर्ष 2015 के आंकड़ें के मुताबिक भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा 68.3 वर्ष, स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष 11.7 साल जबकि स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 6.3 साल और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 5663.5 डॉलर है। इस साल मानव विकास सूचकांक के शुरू हुए 25 वर्ष हो गए। इस अवधि के दौरान भारत ने तमाम चुनौतियों के बावजूद भी उल्लेखनीय तरक्की की है। वर्ष 1990 से अब तक भारत का एचडीआई स्कोर कुल 45.7 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान भारतीयों की औसत जीवन–प्रत्याशा में 10.4 साल, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष में 4.1 साल और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष में 3.3 साल की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 223.4 प्रतिशत का भारी इजाफा हुआ है।

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

राष्ट्रीय आय एवं रोजगार– आय मानव विकास का सबसे अहम घटक है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2013 में भारतीयों का औसत सकल राष्ट्रीय आय 5027 डॉलर प्रतिव्यक्ति था जो 2015 में 12.5 प्रतिशत बढ़कर 5663.5 डॉलर प्रतिव्यक्ति हो गया। इस अवधि में प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी 5238 डॉलर से 9 फीसदी बढ़कर 5730 डॉलर हो गया। साल 2013 में कुल श्रम बल की 3. 6 फीसदी आबादी बेरोजगार थी जो 2015 में घटकर 3.5 फीसदी हो गई है। हालांकि दीर्घ अवधि बेरोजगारी में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। गौरतलब है कि इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कुल अंतर्वाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह हुआ जो वर्ष 2015 में बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया। इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। बीते वर्षों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला है। वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में इंटरनेट और मोबाइल 1 उपयोगकर्ताओं की तादाद में क्रमशः 44 फीसदी और 6 फीसदी का इजाफा हुआ है लेकिन इस अवधि में रोजगार के नए अवसरों के उत्पादन में कमी आयी है और विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक हर पांचवां भारतीय प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम की आमदनी पर गुजर–बसर करता है ।

तालिका – 01 आय/रोजगार सम्बन्धी सूचक

सूचक	2013	2015
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (2011)	5027.1	5663.5
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (2011)	5238	5730
बेरोजगारी (श्रम बल का प्रतिशत)	3.6	3.5
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह (जीडीपी का प्रतिशत)	1.5	2.1

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट– 2014,2015, 2016

स्वास्थ्य सुविधाएं– मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक जन्म के समय भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष 2013 के 66.4 वर्ष के मुकाबले 2015 में बढ़कर 68.3 साल हो गयी। इस दौरान

तालिका 2– स्वास्थ्य संबंधी सूचक सूचक

डाटा, विश्व बैंक (http://data- worldbank-org/indiacatar/ sh-sta- mmart \ location & in)

सूचक	2013	2015
जीवन प्रत्याशा (वर्ष में)	66.4	68.3
नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)	41.4	37.9
शिशु (1–5 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति हजार)	52.7	47.7
मातृ–मृत्यु दर (प्रति लाख)	189*	174
0–5 वर्ष के कुपोषित बच्चे	47.9%	38.7%
टीकाकरण की कमी वाले एक वर्ष से कम उम्र के शिशु		
डीटीपी	12%	10%
चेचक	26%	17%

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट, 2014, 2015, 2016

प्रति हजार नवजात शिशु मृत्यु दर में 8.5 फीसदी, प्रति लाख मातृ मृत्यु दर में 8 फीसदी जबकि 1–5 साल तक के शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम उम्र के कुपोषित बच्चों के अनुपात में 9–9 फीसदी की कमी दर्ज की गयी। वहीं डीटीपी और चेचक के टीके की कमी वाले जन्म से 1 वर्ष तक के शिशु की संख्या में भी क्रमशः 2 और 9 प्रतिशत तक की कमी आयी है। देशभर में मलेरिया और खासकर क्षय रोग से होने वाली मौतों के मामले तेजी से घटे हैं, लेकिन एड्स अभी भी अहम चुनौती बना हुआ है। आजादी के 70 साल बाद भी भारत में अधिकांश आबादी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करने के लिए जूझ रही है।

शैक्षिक उपलब्धियां– शिक्षा मानव विकास का तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 74 फीसदी आबादी ही साक्षर है। पुरुष 80.9 प्रतिशत जबकि स्त्रियां मात्र 64.6 प्रतिशत। मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष 2013 के 11.6 वर्ष के मुकाबले वर्ष 2015 में बढ़कर 11.7 वर्ष हो गया। इस दौरान स्कूली शिक्षा का वर्ष औसत 5.8 वर्ष से बढ़कर 6.3 वर्ष हो गया । इस अवधि में युवाओं (15–24 वर्ष) की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई स्त्रियों और पुरुषों की।

तालिका 3 – शैक्षिक सूचक

एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, मानव स संसाधन विकास मंत्रालय, 2016 (http://mhrd- gov-in/ sites/upload & file/mhrd/filesstatisties / ESG 2016 &0-pdf)

सूचक	2013	2015
स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष	11.6	11.7
स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष	5.8	6.3
साक्षरता (15 से 24 वर्ष)		
स्त्री	74.8%	82.2%
पुरुष	88.4%	91.8%
सकल नामांकन अनुपात* (% में)		
माध्यमिक (14–15 वर्ष)	68.1	78.5
उच्चतर माध्यमिक (16–17)	40.8	54.2
उच्च शिक्षा (18–23)	21.5	24.3

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट, 2014, 2015, 2016

जीवन–स्तर संबंधी धारणाएं– प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट कल्याण की अवधारणा पर एक पूरक सूचकांक भी जारी करता है। सैंपल–सर्वेक्षण आधारित यह सूचकांक व्यक्ति के खुशहाली एवं समाज और सरकार के प्रति लोगों की धारणा से निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2012 की तुलना में भारतीय नागरिक वर्ष 2015 में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन–स्तर की गुणवत्ता से अधिक खुश और संतुष्ट थे। लोगों में सामजिक सुरक्षा की भावना और चयन की आजादी बढ़ी है।

तालिका 4–जीवन स्तर संबंधी धारणाएं

(प्रतिशत संतुष्ट) स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट , 2014, 2015, 2016

सूचक	2012*	2015*
शिक्षा की गुणवत्ता	69	76
स्वास्थ्य की गुणवत्ता	48	62
जीवनस्तर की गुणवत्ता	47	63
आदर्श नौकरी की गुणवत्ता	67	80
सुरक्षा की भावना	61	69
चयन की आजादी	57	75

तालिका 5 – भारत एवं पडोसी देशों की एच. डी. आई. सारणी

मानव विकास सूचक	वर्ष	भारत	पाकिस्तान	बांग्लादेश	नेपाल	श्रीलंका	चान
एच.डी.आई स्कोर	1990	0.428	0.404	0.386	0.378	0.626	0.499
	2015	0.624	0.55	0.579	0.558	0.766	0.738
प्रति व्यक्ति आय (2011)	1990	1751	3193.3	1285.9	1168.4	3639.5	1486.6
	2015	5663	5031.2	3341.5	2337.1	10788.9	13345.5
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष में)	1990	57.9	60.1	58.4	54.3	69.5	69
	2015	68.3	66.4	72	70	75	76
नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)	1990	88.3	106.1	99.7	97.7	18.1	42.1
	2015	37.9	65.8	30.7	29.4	8.4	9.2
शिशु (1-5 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति हजार)	1990	125.8	138.6	143.7	140.7	21	53.8
	2015	47.7	81.1	37.6	35.8	9.8	10.7
स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष	1990	7.6	4.6	5.7	7.5	11.3	8.8
	2015	11.7	8.1	10.2	12.2	14	13.5
स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष	1990	3.0	2.3	2.8	2	8.3	4.8
	2015	6.3	5.1	5.2	4.1	10.9	7.6

स्रोत : डाटा, मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी (http://hdrundp-org/en/dat)46

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 व वर्ष 2018 की रिपोर्ट में कुल 149 देशों के इस सर्वे में भारत को 108वां स्थान मिला है– वर्ष 2017 में भी भारत का यही रैंक था, जबकि 2016 में वह 21 स्थान ऊपर 87वें स्थान पर था। व वर्ष 2017 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में गिरावट के पीछे मुख्यत : राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और बुनियादी साक्षरता के क्षेत्रों में लैंगिक असमानता बढ़ने को जिम्मेदार ठहराया गया था व रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों के बीच बांग्लादेश 48वें स्थान के साथ सबसे अच्छी स्थिति में है। वर्ष 2017 में भी बांग्लादेश ही दक्षिण एशिया में लैंगिक असमानत रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ रहा था, पिछले वर्ष बांग्लादेश की रैंकिंग 47 थी ।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 (Global Gender Gap IndeÛ 2020 % GGI 2020) में भारत को 112वीं रैंक प्रदान हुयी है। वर्ष 2018 में भारत 108वें स्थान पर था। इस तरह भारत चार रैंक नीचे चला गया है। इस सूचकांक में भारत अपने कई पड़ोसियों से भी पीछे है। बांग्लादेश (50वें), नेपाल (101), श्रीलंका (102) व चीन (106) से भारत पीछे है। सूचकांक में सर्वोच्च रैंकिंग आइसलैंड को प्राप्त हुयी है और विगत 11वर्षों से यह विश्व का सर्वाधिक लैंगिक–तटस्थ देश रहा है। उसके पश्चात नॉर्वे, फिनलैंड व स्वीडेन की रैंकिंग है। विश्व के 153 देशों में यमन सबसे नीचे है ।

रैंकिंग	देश
1	नॉर्वे
2	स्विट्जरलैंड
3	ऑस्ट्रेलिया
4	आयरलैंड
5	जर्मनी
6	आइसलैंड
7	हॉन्गकॉन्ग
9	स्वीडन
9	सिंगापुर
10	नीदरलैंड

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 – भारत 112वें स्थान पर विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 (Global Gender Gap IndeÛ 2020 : GGI 2020) में भारत को 112वीं रैंक प्रदान हुयी है। वर्ष 2018 में भारत 108वें स्थान पर था। इस तरह भारत चार रैंक नीचे चला गया है।

भारत में असमानता का आलम यह है कि ऑक्सफैम

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल भारत में जितनी संपत्ति पैदा हुई, उसका 73 प्रतिशत हिस्सा देश के 1 फीसदी धनाढ्य लोगों के हाथों में चला गया, जबकि नीचे के 67 करोड़ भारतीयों को इस संपत्ति के सिर्फ एक फीसदी यानी सौवें हिस्से से संतोष करना पड़ा है। सचाई यह है कि भूमंडलीकरण के दौर में सरकार की भूमिका कम हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण ने धनाढ्य वर्ग को ज्यादा लाभ पहुंचाया है। गरीबों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाएं नौकरशाही के भरोसे हैं, जिसमें भारी भ्रष्टाचार है। इसलिए जो नीतियां बनती भी हैं, वे पूरी तरह लागू नही हो पातीं। प्राय : योजनाओं में सरकारी संसाधन की बंदरबांट हो जाती है। वक्त आ गया है जब सरकार सचाई यह है कि भूमंडलीकरण के दौर में सरकार की भूमिका कम हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण ने धनाढ्य वर्ग को ज्यादा लाभ पहुंचाया है। गरीबों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाएं नौकरशाही के भरोसे हैं, जिसमें भारी भ्रष्टाचार है। इसलिए जो नीतियां बनती भी हैं, वे पूरी तरह लागू नहीं हो पातीं। प्रायः योजनाओं में सरकारी संसाधन की बंदरबांट हो जाती है। वक्त आ गया है जब सरकार गरीबों के लिए बनी तमाम कल्याणकारी योजनाओं को सख्ती से लागू करे। तभी मानव सूचकांक में पीछे रहने का हमारा कलंक दूर होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मानव विकास रिपोर्ट, 2014, 2015, 2016 और 2019.
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2016 – 17, 2018 – 19.
3. प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो।
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
5. https://www-amarujala-com > tags
6. https://www-gstimes-in >hindi& inter

*****